

पुस्तकालयों में आपदा जोखिम प्रबंधन की चुनौतियाँ: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

अंकिता गुप्ता¹, डॉ. रितु सिंह²

¹ शोधार्थी, डॉ. एस. आर. रंगनाथन इंस्टिट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एण्ड इनफार्मेशन साइंस, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी, उत्तर प्रदेश, भारत

² विभागाध्यक्ष एवं सह आचार्य, डॉ. एस. आर. रंगनाथन इंस्टिट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एण्ड इनफार्मेशन साइंस, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

आपदाएँ संपत्ति, मानव जीवन तथा सामाजिक सेवाओं की निरंतरता पर गंभीर प्रभाव डालती हैं एवं सांस्कृतिक एवं ज्ञान-संस्थानों के समक्ष जटिल चुनौतियाँ प्रस्तुत करती हैं, विशेषतः पुस्तकालयों के संदर्भ में, जो ज्ञान-संरक्षण, सांस्कृतिक विरासत तथा संस्थागत स्मृति के प्रमुख संरक्षक हैं। प्राकृतिक एवं मानव-जनित आपदाओं की बढ़ती तीव्रता ने पुस्तकालयों में आपदा प्रबंधन नीति एवं संस्थागत ढाँचे के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता को रेखांकित किया है। इस संदर्भ में पुस्तकालयों में आपदा जोखिम प्रबंधन (Disaster Risk Management) का प्रभावी कार्यान्वयन अत्यंत आवश्यक हो जाता है।

प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय एवं भारतीय स्तर पर उपलब्ध आपदा प्रबंधन नीतियों एवं दिशानिर्देशों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है। अध्ययन में अंतरराष्ट्रीय संगठनों जैसे इफला, यूनेस्को, एएलए, तथा संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (UNDRR) के दिशा-निर्देशों का विश्लेषण किया गया है, साथ ही भारतीय परिप्रेक्ष्य में आपदा प्रबंधन नियम, 2005, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (NDMP) एवं जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) का मूल्यांकन किया गया है।

अध्ययन में पाया गया कि अंतरराष्ट्रीय नीतियाँ पुस्तकालय-विशिष्ट, संरचित एवं तकनीकी रूप से उन्नत हैं, जबकि भारतीय नीतिगत ढाँचा विधिक रूप से सुदृढ़ होते हुए भी पुस्तकालयों के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देशों के अभाव से ग्रस्त है। यह शोध नीतिगत अंतरालों की पहचान करते हुए भारतीय पुस्तकालयों के लिए एक समेकित, संदर्भ-संवेदी एवं प्रत्यास्थ आपदा जोखिम प्रबंधन ढाँचे की आवश्यकता पर बल देता है।

मूल शब्द: आपदा प्रबंधन, पुस्तकालय, संग्रह संरक्षण, जोखिम प्रबंधन, पुस्तकालय सुरक्षा

पुस्तकालय ज्ञान के संरक्षण, संसाधनों तक पहुँच उपलब्ध कराने तथा शैक्षणिक एवं अनुसंधान गतिविधियों को समर्थन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सांस्कृतिक विरासत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करने का प्रभावी माध्यम भी हैं (Ansari, 2024) [1]। पुस्तकालय अपने संग्रह में मुद्रित एवं डिजिटल दोनों रूपों में मूल्यवान, दुर्लभ तथा संवेदनशील सामग्रियों को सुरक्षित रखते हैं। इन बहुआयामी भूमिकाओं के कारण पुस्तकालयों का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है, अतः उन्हें संभावित आपदाओं से सुरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है (Bansal, 2015) [3]। पुस्तकालय प्रबंधन में किसी भी प्रकार की त्रुटि या लापरवाही संसाधनों तथा आर्थिक संरचना को गंभीर क्षति पहुँचा सकती है। किसी भी आपदा के प्रभाव से पूर्णतः उबरने में प्रायः लंबा समय लग जाता है। ज्ञान और विरासत के संरक्षक के रूप में पुस्तकालयों की संपत्तियों का संरक्षण सामुदायिक ज्ञान-विकास तथा राष्ट्रीय प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है।

पुस्तकालयों में आपदा प्रबंधन

आपदाएँ समकालीन वैश्विक समाज के समक्ष एक जटिल, बहुस्तरीय एवं संरचनात्मक चुनौती के रूप में उभरी हैं। इनका प्रभाव केवल मानव जीवन एवं भौतिक संपदा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि संस्थागत संरचना, सांस्कृतिक धरोहरों तथा ज्ञान-आधारित संरचनाओं पर भी गहरा और दीर्घकालिक प्रभाव डालता है। पुस्तकालय, जो ज्ञान-संरक्षण, सूचना-प्रसारण, शोध-सहायता तथा सामाजिक स्मरण के संस्थान हैं, यह प्राकृतिक एवं मानव-निर्मित दोनों प्रकार की आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील माने जाते हैं। प्राकृतिक आपदाओं में चक्रवात, भूकंप, आग, तूफान, बाढ़, सुनामी तथा महामारी जैसे

घटनाचक्र सम्मिलित हैं, जबकि मानव-निर्मित आपदाओं में चोरी, तोड़फोड़, तकनीकी विफलता, रासायनिक जोखिम, साइबर आक्रमण तथा लापरवाही प्रमुख हैं (Ilo et al., 2020) [8]। ये सभी कारक पुस्तकालयों को आंशिक या पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त कर सकते हैं। आपदा जोखिम प्रबंधन (DRM) ढाँचे के अंतर्गत पुस्तकालयों को ऐसे अनुकूलन शील (Adaptive) संगठनों के रूप में देखा जाता है, जो जोखिम न्यून करण, प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति को अपनी कार्यप्रणाली में समाहित करते हैं, ताकि आपदाओं के प्रभाव के बावजूद सेवाओं की निरंतरता और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके (श्रवीदेवद – स्मम, 2025)। यह परिभाषा उनके विकसित होते और प्रत्यास्थ स्वरूप को दर्शाती है।

इस प्रकार आपदाएँ पुस्तकालय तंत्र पर व्यापक और दीर्घकालिक प्रभाव डालती हैं। पुस्तकालय में वर्तमान समय में साइबर आक्रमण, प्रणाली विफलता तथा सॉफ्टवेयर संबंधी बाधाएँ पुस्तकालय प्रणाली के सुचारु संचालन के लिए उभरते हुए गंभीर खतरे के रूप में सामने आए हैं (Dada et al., 2025) [5]। अतः आधुनिक पुस्तकालयों के लिए आपदा प्रबंधन रणनीतियों में पारंपरिक भौतिक खतरों के साथ-साथ डिजिटल एवं तकनीकी जोखिमों को भी समान महत्व देना आवश्यक हो गया है। इस परिप्रेक्ष्य में आपदा जोखिम प्रबंधन केवल तात्कालिक प्रतिक्रिया की प्रक्रिया न होकर एक समेकित, पूर्वानुमान और रणनीतिक नीतिगत आवश्यकता के रूप में स्थापित होता है। प्रभावी जोखिम प्रबंधन संस्थागत प्रत्यास्थता (Institutional Resilience), सेवा-निरंतरता और दीर्घकालिक स्थिरता को सुदृढ़ करने का आधार प्रदान करता है।

वैश्विक स्तर पर आपदा जोखिम प्रबंधन को नीति-आधारित एवं संरचित ढाँचे में विकसित किया गया है। भारत में आपदा प्रबंधन

नियम, 2005 के माध्यम से विधिक ढाँचा स्थापित किया गया, किंतु पुस्तकालयों के संदर्भ में विशिष्ट दिशानिर्देशों की कमी विद्यमान है। यह अध्ययन गुणात्मक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपनाता है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध आपदा प्रबंधन दिशानिर्देशों, नीति दस्तावेजों, केस स्टडीज और मानकों की समीक्षा की गई है।

उद्देश्य

1. अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध पुस्तकालय-विशिष्ट DRM नीतियों एवं मानकों का विश्लेषण करना।
2. भारतीय आपदा प्रबंधन नीति ढाँचे का अध्ययन करना।
3. दोनों स्तरों के बीच तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करना।

साहित्य समीक्षा

Chigwada और Ngulube (2025) ^[1] अपने शोध में शोधकर्ताओं ने उन कारकों की पहचान की जो प्रभावी आपदा प्रबंधन को सक्षम या बाधित करते हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि पुस्तकालयों को शैक्षणिक संदर्भ के अनुरूप आपदा तैयारी एवं प्रबंधन प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। यह अध्ययन एक व्यवस्थित साहित्य समीक्षा (Systematic Literature Review) के रूप में किया गया। इसमें पाया गया कि पुस्तकालयों को आग, बाढ़, डिजिटल समस्याओं तथा महामारी जैसी अनेक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। अध्ययन में सुझाव दिया गया कि पुस्तकालयों को बेहतर आपदा प्रबंधन योजना विकसित करनी चाहिए, संरचना में निवेश करना चाहिए तथा क्षमता-विकास पहलों जैसे स्टाफ प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी के उपयोग और सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए।

Dada et al. (2025) ^[5] अपने शोध में लेखकों ने बताया कि पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र सूचना, ज्ञान और संस्कृति के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, किन्तु वे आपदाओं से अछूते नहीं हैं, जो उनके संग्रह और सेवाओं को प्रभावित करती हैं। इस अध्ययन में यह विश्लेषण किया गया कि आपदा जोखिम प्रबंधन (DRM) किस प्रकार पुस्तकालयों को संभावित जोखिमों का पूर्वानुमान लगाने में सहायता कर सकता है। इसमें DRM की अवधारणा, पुस्तकालयों में इसके उपयोग तथा इसके कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन किया गया। अध्ययन का निष्कर्ष था कि आपातकालीन प्रतिक्रिया संगठनों के साथ सहयोग स्थापित करना, नियमित प्रशिक्षण आयोजित करना, नीतियों का निर्माण करना तथा संसाधनों की सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना आवश्यक है। इन उपायों से पुस्तकालय संकट के समय भी अपनी सेवाएँ जारी रख सकते हैं और प्रत्यास्थ बने रह सकते हैं।

Ansari et al. (2024) ^[1] अपने अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पुस्तकालयों में घटित आपदाओं पर उपलब्ध साहित्य की एक व्यवस्थित समीक्षा की। इस अध्ययन में विभिन्न प्रकार की आपदाओं, उनके पुस्तकालयों पर प्रभाव तथा जोखिम को कम करने के लिए विभिन्न प्रकार के पुस्तकालयों द्वारा अपनाई गई रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। साथ ही, आपदा जोखिम न्यून करण में सहायक उपलब्ध संसाधनों को भी रेखांकित किया गया तथा मौजूदा अध्ययनों में पाए जाने वाले प्रमुख विषयों एवं प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया गया। अध्ययन का निष्कर्ष था कि इन हानियों को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाना महत्वपूर्ण है, जैसे पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के पाठ्यक्रम में आपदा प्रबंधन को शामिल करना तथा सभी पुस्तकालयों में 'नीति-से-प्रयोग' (policy-in-practice) के रूप में आपदा प्रबंधन को लागू करना।

Gohain और Tariang (2023) ^[6] का शोध अध्ययन असम के शैक्षणिक पुस्तकालयों पर आधारित था, जिसमें मुद्रित संग्रहों के आपदा प्रबंधन का परीक्षण किया गया। इसमें विशेष रूप से स्टाफ की जागरूकता, तैयारी और आपदा प्रबंधन योजनाओं की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया गया। डेटा संग्रह के लिए प्रश्नावली आधारित सर्वेक्षण पद्धति का उपयोग किया गया। अध्ययन में पाया गया कि वरिष्ठ पेशेवरों को आपदा योजना की समझ थी, जबकि अधिकांश सहायक स्टाफ में जागरूकता का अभाव था। यद्यपि असम बाढ़ और आग दोनों प्रकार की आपदाओं के प्रति संवेदनशील है, फिर भी पुस्तकालय इन आपदाओं से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं थे। औपचारिक आपदा प्रबंधन योजनाओं और प्रशिक्षित स्टाफ की कमी प्रमुख चुनौतियों के रूप में सामने आई।

Kushawaha और Singh (2022) ^[11] ने उत्तर प्रदेश के केंद्रीय पुस्तकालयों में आपदाओं से पुनर्प्राप्ति (Recovery) की रणनीतियों का अध्ययन किया। उनके अध्ययन में पुस्तकालयों के सामने आने वाले जोखिमों, खतरों और आपदाओं का विश्लेषण किया गया तथा प्राकृतिक, मानव-निर्मित और तकनीकी आपदाओं के पहले, दौरान और बाद में अपनाई जाने वाली रणनीतियों की जांच की गई। इसके साथ ही, आपदा के बाद पुस्तकालयों को आने वाली समस्याओं का भी अध्ययन किया गया। शोध में पाया गया कि उत्तर प्रदेश के केंद्रीय पुस्तकालयों में औपचारिक आपदा प्रबंधन योजनाओं का अभाव मुख्यतः सीमित बजट, अपर्याप्त एवं अकुशल स्टाफ तथा आवश्यक उपकरणों की कमी के कारण है। Shahane (2022) ^[15] ने अपने अध्ययन में 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय पुस्तकालयों पर सर्वेक्षण किया, ताकि उनकी आपदा प्रबंधन एवं तैयारी की स्थिति का आकलन किया जा सके। अध्ययन से पता चला कि केवल 15% पुस्तकालयों ने आपदा का सामना किया था, जबकि मात्र 20% पुस्तकालयों के पास लिखित आपदा प्रबंधन योजनाएँ थीं। साथ ही यह भी पाया गया कि 62% पुस्तकालयों के पास अपने संग्रह और संरचना के लिए कोई बीमा सुरक्षा नहीं थी, जबकि 85% पुस्तकालयों में कुछ हद तक सुरक्षा उपकरण जैसे CCTV कैमरे और अग्निशामक यंत्र स्थापित थे। इस अध्ययन में प्रमुख चुनौतियाँ थीं—स्टाफ प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अभाव, आपातकालीन प्रोटोकॉल की अनुपस्थिति, तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देशों का अनुपालन न होना। यह शोध पुस्तकालयों में आपदा प्रबंधन के लिए व्यवस्थित तैयारी की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

उपलब्ध साहित्य की समीक्षा करने के बाद ये पता चलता है कि भारत में ज्यादातर संस्थाओं के पास कोई भी आपदा प्रबंधन योजना नहीं है, और ना ही कोई भी दिशानिर्देश उपलब्ध है। इस कारणवश देश – विदेश के मानकों और नीतियों का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन करना महत्वपूर्ण हो गया है, जिससे ये पता चल सके की कौन-सी संस्थाएँ पुस्तकालय के लिए आपदा प्रबंधन की नीतियों और मानकों पर कार्य कर रही हैं।

अनुसंधान पद्धति

यह अध्ययन द्वितीयक स्रोतों (Secondary Sources) पर आधारित है। नीति दस्तावेजों, अंतरराष्ट्रीय नीतियों, दिशानिर्देशों, अधिनियमों, मानकों तथा शैक्षणिक साहित्य का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है।

अंतरराष्ट्रीय एवं भारतीय नीतियों, दिशानिर्देश और मानक: विश्लेषण

■ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नीति, दिशानिर्देश एवं मानक

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपदा जोखिम प्रबंधन (DRM) को एक बहुआयामी समस्या मानते हुए नीतिगत ढाँचे, दिशानिर्देशों और मानकों का विकास किया गया है। इन मानकों में पुस्तकालयों,

संग्रहालयों और सांस्कृतिक संस्थानों हेतु जोखिम मूल्यांकन, तैयारी, प्रतिक्रिया तथा पुनर्प्राप्ति दिशानिर्देश शामिल हैं। पुस्तकालय संघों और संस्थानों का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ (IFLA)

इफला (IFLA) ने आपदा प्रबंधन को समझने के 5 उपाय बताए हैं –

1. जोखिम का आकलन,
2. रोकथाम और सुरक्षा,
3. तैयारी,
4. प्रतिक्रिया
5. पुनर्प्राप्ति

सबसे पहले यह देखा जाता है कि किस प्रकार के खतरे हो सकते हैं और वे कितने गंभीर हो सकते हैं। इसके बाद ऐसे उपाय किए जाते हैं जिससे नुकसान को जितना हो सके कम किया जा सके। तैयारी के चरण में योजना बनाना, कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना और आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करना शामिल होता है, ताकि आपदा आने पर तुरंत सही कदम उठाए जा सकें। जब वास्तव में आपदा आती है, तो उसी तैयारी आधार पर त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया दी जाती है। अंत में, पुनर्प्राप्ति के दौरान पुस्तकालय की सेवाओं, संसाधनों और भवन को फिर से सामान्य स्थिति में लाने का प्रयास किया जाता है।

- जोखिम पहचान, प्राथमिकता सूची (Priority Salvage List), आपातकालीन दल
- डिजिटल करण एवं सेवा निरंतरता योजनाएँ
- कर्मचारी प्रशिक्षण और प्रबंधन

विश्लेषण

इफला का दृष्टिकोण पुस्तकालय-विशिष्ट एवं व्यावहारिक है। यह निर्देश जोखिम प्रबंधन को स्टाफ, संरचना और सामग्री बचाव रणनीतियों के साथ जोड़ता है, जो वैश्विक सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों के अनुरूप हैं (McIlwaine, 2016) ^[16]।

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO)

- विश्व धरोहर स्थलों के लिए आपदा जोखिम प्रबंधन
- संग्रह संरक्षण के लिये जोखिम प्रबंधन
- पूर्व-तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति
- प्रशिक्षण, संसाधन साझेदारी और तकनीकी सहायता

विश्लेषण

यूनेस्को (UNESCO) का फ्रेमवर्क सांस्कृतिक संरक्षण को प्राथमिकता देता है और पुस्तकालयों को सांस्कृतिक स्मृति संस्थान के रूप में मानता है, जिससे समग्र क्टड रणनीति का विस्तार होता है (UNESCO, 2010)।

अमेरिकी पुस्तकालय संघ (ALA)

- पुस्तकालय आपदा योजना और पुनर्प्राप्ति
- भवन सुरक्षा, आपातकालीन उपकरण
- स्टाफ प्रशिक्षण एवं प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल
- नियमित अभ्यास, परीक्षण और मूल्यांकन

विश्लेषण

एलए (ALA) का मॉडल स्पष्टतल व्वमतंजपवदे वे दृष्टिकोण प्रदान करता है जिसे पुस्तकालयों द्वारा अपनी संस्थागत आपदा जोखिम प्रबंधन (DRM) नीति में प्रत्यक्ष रूप से लागू किया जा सकता है।

सेंडई रूपरेखा (Sendai Framework) (UNDRR)

- जोखिम की पहचान
- नीति-निर्माण में क्टड का समावेश
- पुनर्प्राप्ति में सुधार
- सामुदायिक भागीदारी

विश्लेषण

यह ढाँचा आपदा जोखिम प्रबंधन (DRM) को सार्वभौमिक स्तर पर मान्यता देता है, जो पुस्तकालय आपदा जोखिम प्रबंधन (DRM) के लिए व्यापक नीतिगत संदर्भ प्रदान करता है (UNDRR, 2015)।

आईएसओ (ISO) 22301:2019

यह मानक पुस्तकालयों के लिए संस्थागत निरंतरता, आपदा जोखिम प्रबंधन (DRM) योजना और प्रक्रियाओं को एक मानकीकृत दृष्टिकोण में स्थापित करने में मदद करता है (ISO, 2019)।

पुस्तकालय एवं अभिलेखागार, कनाडा

- संग्रह संरक्षण, डिजिटल जीवन चक्र
- जोखिम मूल्यांकन, आपदा प्रतिक्रिया

भारतीय नीतियाँ, दिशानिर्देश और आपदा जोखिम प्रबंधन ढाँचे

भारत में आपदा जोखिम प्रबंधन (DRM) का कानूनी एवं प्रशासनिक स्तरीय ढाँचा विकसित है, किन्तु पुस्तकालय-विशिष्ट नीतियाँ प्राथमिक रूप से अनुपस्थित हैं।

1. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)

- आपदा जोखिम प्रबंधन के प्रमुख तत्व: जोखिम पहचान, क्षमता निर्माण,
- विभागीय आपदा जोखिम प्रबंधन योजना, सार्वजनिक चेतना
- पुस्तकालयों के लिए समर्पित मार्ग दर्शिका नहीं हैं।
- विश्लेषण: NDMA, आपदा जोखिम प्रबंधन दिशा-निर्देश व्यापक हैं परन्तु पुस्तकालयों को लागू करते समय अनुकूलन आवश्यक है।

2. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (NDMP)

- बहु-जोखिम रणनीति
- पुनर्प्राप्ति, प्रारंभिक चेतावनी तंत्र, सामुदायिक आउटरीच

विश्लेषण

NDMP, Sendai Framework के अनुरूप है, किन्तु पुस्तकालय-विशिष्ट आपदा जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया नहीं दर्शाता है।

3. जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP)

- स्थानीय स्तर पर आपदा जोखिम प्रबंधन योजना
- सार्वजनिक संस्थान, भवन सुरक्षा

विश्लेषण

DDMP पुस्तकालयों को स्थानीय आपदा जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में शामिल कर सकता है, परन्तु नीति के रूप में स्पष्ट नहीं है।

4. आपदा प्रबंधन नियम, 2005

- कानूनी आपदा जोखिम प्रबंधन आधार
- राष्ट्रीय, राज्य, जिला आपदा जोखिम प्रबंधन संरचना

विश्लेषण

आपदा प्रबंधन नियम 2005, आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए मजबूत कानूनी ढाँचा प्रदान करता है, परन्तु पुस्तकालय-विशेष आपदा जोखिम प्रबंधन आवश्यकताओं का प्रत्यक्ष समाधान नहीं करता है।

विश्लेषणात्मक अवलोकन

1. नीतिगत विशिष्टता: अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ (IFLA, ALA, ALIA) पुस्तकालय कूट के लिए विशेष दिशा-निर्देश प्रदान करती हैं, पर भारत में यह स्पष्ट नहीं है।
2. संरक्षण का दायरा: यूनेस्को और सेंडई रूपरेखा, आपदा जोखिम प्रबंधन को सांस्कृतिक एवं सामुदायिक दृष्टिकोण से समाहित करते हैं।
3. मानकीकरण: ISO 22301 मानकीकृत ढाँचा प्रदान करता है, जो पुस्तकालय में आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए एक मजबूत प्रविष्टि है।
4. भारतीय आपदा जोखिम प्रबंधन ढाँचा: कानूनी एवं व्यापक रूप से मजबूत है पर पुस्तकालय-विशिष्ट अनुपालन ने स्पष्ट दिशा न दी है।

नीतिगत एवं संस्थागत सुझाव राष्ट्रीय स्तर

1. पुस्तकालय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश का निर्माण NDMA द्वारा पृथक रूप से किया जाए।
2. आपदा प्रबंधन नियम, 2005 के अंतर्गत सांस्कृतिक एवं सूचना संस्थानों को विशेष श्रेणी में सम्मिलित किया जाए।
3. NDMP में पुस्तकालय-विशिष्ट जोखिम आकलन एवं डिजिटल संरक्षण अनुभाग जोड़ा जाए।
4. ISO 22301 आधारित BCMS मॉडल को विश्वविद्यालय एवं सार्वजनिक पुस्तकालयों में अनिवार्य किया जाए।

स्थानीय स्तर

1. DDMP में पुस्तकालयों का स्पष्ट उल्लेख हो।
2. जिला प्रशासन एवं पुस्तकालयों के मध्य समन्वय तंत्र विकसित किया जाए। जलवायु परिवर्तन आधारित जोखिम मान चित्रण किया जाए।

संस्थागत स्तर

1. प्रत्येक पुस्तकालय में आपदा प्रतिक्रिया टीम गठित की जाए।
2. डिजिटल बैकअप, क्लाउड स्टोरेज एवं ऑफ-साइट डेटा संरक्षण अपनाया जाए।
3. प्राथमिकता संरक्षण सूची (Priority Salvage List) तैयार की जाए।
4. नियमित मॉक ड्रिल एवं स्टाफ प्रशिक्षण आयोजित किया जाए।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

1. इफला और यूनेस्को के साथ तकनीकी सहयोग कार्यक्रम विकसित किए जाए।
2. अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण मॉड्यूल भारतीय पुस्तकालय विज्ञान पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाए।
3. क्षेत्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन नेटवर्क स्थापित किए जाए।

डिजिटल संरक्षण

1. डिजिटल संसाधनों हेतु क्लाउड बैकअप एवं साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल अनिवार्य किए जाए।
2. ISO 22301 आधारित सेवा-निरंतरता मॉडल अपनाया जाए।

क्षमता निर्माण एवं सहयोग

1. पुस्तकालय अध्यक्ष एवं स्टाफ के लिए प्रमाणित प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किए जाए।
2. इफला एवं यूनेस्को के दिशा-निर्देशों को स्थानीय संदर्भ में अनुकूलित किया जाए।

3. जिला स्तर पर DDMP में पुस्तकालयों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

निष्कर्ष

यह अध्ययन दर्शाता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकालयों के लिए आपदा जोखिम प्रबंधन एक परिपक्व एवं संरचित नीति क्षेत्र के रूप में विकसित हो चुका है। इफला, एएलए, तथा यूनेस्को जैसे संस्थानों ने पुस्तकालय-विशिष्ट दिशा निर्देश, प्रशिक्षण मॉडल, डिजिटल संरक्षण रणनीतियाँ एवं सेवा-निरंतरता ढाँचे विकसित किए हैं। इसके विपरीत, भारत में आपदा प्रबंधन नियम, 2005 तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा स्थापित नीति ढाँचा व्यापक एवं विधिक रूप से सुदृढ़ है, किन्तु पुस्तकालयों के लिए पृथक दिशानिर्देशों का अभाव स्पष्ट रूप से नीतिगत अंतराल को इंगित करता है।

अतः यह आवश्यक है कि भारत में पुस्तकालयों के लिए एक समर्पित आपदा जोखिम प्रबंधन नीति विकसित की जाए, जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो, किन्तु भारतीय सामाजिक, सांस्कृतिक एवं प्रशासनिक संदर्भों के अनुकूल भी हो। इससे न केवल सूचना संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा भी सुदृढ़ होगी।

संदर्भ सूची

1. Ansari AJ, Vaidya P, Malik BA, Ali PMN. Preparing for the unthinkable: A systematic look at disaster preparedness in libraries. *International Journal of Disaster Risk Reduction*,2024;108:104551. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2024.104551>
2. American Library Association. *LibGuides: Library Disaster Preparedness & Response*. American Library Association,2020. <https://libguides.ala.org/disaster/home>
3. Bansal J. Disaster management in libraries: An overview. *Gyankosh- The Journal of Library and Information Management*,2015;6(1):9. <https://doi.org/10.5958/2249-3182.2015.00002.7>
4. Chigwada J, Ngulube P. Disaster Preparedness and Management Practices in Academic Libraries in Context. *International Journal of Disaster Management*,2025;7(3): Article 3. <https://doi.org/10.24815/ijdm.v7i3.40580>
5. Dada KSJ, Hamza JM, Mohammed HA. Disaster Risk Management in Libraries and Information Centers: Global Strategies, Challenges, Policy and Recommendations. *International Journal of Disaster Risk Management*,2025;7(1):203–214. <https://doi.org/10.18485/ijdrm.2025.7.1.11>
6. Gohain A, Tariat BL. Disaster Management of Print Collections in Academic Libraries of Assam: A study. *Journal of Indian Library Association*,2023;59(3):80–92.
7. Government of India, Ministry of Law and Justice. *The Disaster Management Act, 2005 (Act No. 53 of 2005)*,2005. <https://ndmindia.mha.gov.in/ndmi/images/The%20Disaster%20Management%20Act,%202005.pdf>
8. Ilo PI, Nkiko C, Izuagbe R, Furfuri IM. Librarians' perception of disaster preparedness as precursor for effective preservation and conservation of library resources in Nigerian university libraries. *International Journal of Disaster Risk*

- Reduction,2020:43:101381. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2019.101381>
9. International Organization for Standardization. ISO 22301:2019. Security and resilience-Business continuity management systems-Requirements,2019. <https://www.iso.org/standard/75106.html>
 10. Johnson K, Lee M. Adaptive strategies in library disaster management: A 21st-century perspective. *Library Management*,2025:46(1):12–25.
 11. Kushawaha PP, Singh MP. Disaster Experience and Recovery Strategies in Central University Libraries of Uttar Pradesh: An Analytical Study. *Journal of Information Management*,2022:9(1):20. <https://doi.org/10.5958/2348-1773.2020.00001.6>
 12. McIlwaine J. IFLA disaster preparedness and planning: A brief manual. International Federation of Library Associations and Institutions,2016. <https://www.ifla.org/files/assets/pac/ipi/ipi6-en.pdf>
 13. National Disaster Management Authority. National policy on disaster management. Government of India,2009. https://nidm.gov.in/PDF/policies/ndm_policy2009.pdf
 14. National Disaster Management Authority. National disaster management plan. Government of India,2016. <https://ndma.gov.in/sites/default/files/PDF/Guidelines/NDMP-2019.pdf>
 15. Shahane S. Disaster planning in the libraries of Central Universities at India: An analysis. *Research Journal of Library Sciences*,2022:10(2):1–10.
 16. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Managing disaster risks for world heritage,2010. <https://whc.unesco.org/en/disaster-risk-reduction/>
 17. United Nations Office for Disaster Risk Reduction. Sendai framework for disaster risk reduction 2015–2030,2015. <https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030>